

प्रेषक,

सी० भास्कर,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,  
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2.

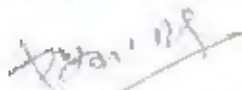
देहरादून: दिनांक: 24 अगस्त, 2007

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये स्वीकृत आय-व्ययक के विरुद्ध धनराशि निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 711/उपायाति/उम्प्रवि०/शासन बजट(07-08), दिनांक 09.08.2007 के सदर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजना/राज्य योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अंश से परिवर्तकों के अधीन एल.टी. सुदृढीकरण इत्यादि कार्य हेतु ऋण के रूप में वांछित धनराशि के सापेक्ष रु० 03,80,00,000.00 (रु० तीन करोड़ अरसी लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु निर्मांकित शर्तों के अधीन आपके निवेदन में रखने की सहस्र स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यों का विस्तृत आगमन, कार्यों का विस्तृत विवरण, समयबद्ध समय सारिणी, लागत, लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का विस्तृत विवरण शासन को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उक्त बिन्दुओं पर जस्ताविका विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय एवं कार्यों का क्रियान्वयन परियोजना मॉड में वर्धोचित बारचार्ट/पोर्ट चार्ट आदि पूर्व में निर्दिष्ट कर किया जायेगा।
- 2- उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, संबंधित ग्राम प्रधानों को कार्य कराने से पूर्व व बाद में उपलब्ध कराया जायेगा तथा वर्धोचित माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त कार्यों एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेगी।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।
- 5- व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैन्युअल, फाईनेन्सियल हेण्डबुक स्टार पर्वज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय डी०जी०एस० एण्ड डी० अथवा टेंडर/कुटेशन विषयक निम्नो का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
- 6- कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगमन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 7- स्वीकृत कार्यों की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 8- आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु लाबाई द्वारा ऋण रु० 6.5% की दर निर्धारित है। इस ऋण पर भी व्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है तथा वित्तम्ब की दर में 1.0% अतिरिक्त वित्तम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की कम्पनी 10 वार्षिक किस्तों में (व्याज सहित) माह अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होगा।
- 10- प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनपदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेगा।



11- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० जब भी किश्तों का भुगतान करे ब्याज भी अवश्य जमा करे एवं महालेखाकार कार्यालय एवं शासन के ऊर्जा सैल को निम्न दिन्दुओं पर सूचना भेजे:-

1- जोषागार का नाम, 2- बालान सं०, 3- जमा धनराशि, किश्त ब्याज, 4- शासनादेश संख्या और एन०एन०आर० का संदर्भ, 5- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

12- ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से अवश्य करे तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा जे।

13- भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।

14- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2008 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का मासिक रूप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

15- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर पी०एन०ए० में रखी जायेगी जिसका आहरण आवश्यकता एवं वार्षिक प्रगति के आधार पर तीन किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ही दूसरी किश्त का आहरण किया जायेगा। इसी प्रकार तीसरी किश्त का आहरण भी द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर किया जायेगा। मासिक रूप से योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

16- इस धनराशि से सर्वप्रथम गत वर्ष में 80 प्रतिशत किए गये कार्यों को पूर्ण किया जायेगा।

17- अवमुक्त की जा रही धनराशि का शासन को प्रस्तुत प्रस्ताव में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य अनुसार व्यय किया जायेगा।

18- स्वीकृत धनराशि बालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय के अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत लघुवित्तिय 6801-विजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारपण एवं वितरण-आयोजनागत-180-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० को ऋण-00-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अक्षासकीय सं० 324/XXVII(2)/2007, दिनांक 23 अगस्त, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी० भास्कर)  
अपर सचिव

संख्या: 943  
1(2)/2007-06(1)/34/06, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4- कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-2
- 6- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग।
- 7- सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 8- प्रभारी एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
- 9- विशेष सैल, ऊर्जा।
- 10- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एम०एम० सेमवाल)  
अनु सचिव